



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2019/अग्रहायण 20, 1941

No. 458]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2019/AGRAHAYANA 20, 1941

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### अधिसूचना

मुम्बई, 29 नवम्बर, 2019

**सं. टीएमपी/20/2010-केपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की वर्तमान दर संरचना की वैधता का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, विस्तार करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### मामला संख्या: टीएमपी/20/2010-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

### आदेश

(नवम्बर, 2019 के 29वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की वैधता के विस्तार के लिए डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2. डीपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता का पिछला विस्तार डीपीटी के अनुरोध पर 03 मई, 2019 के आदेश संख्या टीएमपी/20/2010-केपीटी के द्वारा 30 सितम्बर, 2019 तक अथवा डीपीटी द्वारा दायर

किए गये प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित किराये की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, किया गया था।

3.1 संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश (एलपीजी) 2014 का पैरा 5.7 बताता है कि यह नीति डीपीटी, मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) टाउनशिपों से संबंधित भूमि को छोड़कर, जिनके लिए अलग से नीति बनायी जाएगी, सभी महापत्तनों के लिए लागू है।

3.2 इस संबंध में, एमओएस को एक संदर्भ भेजा गया था, एमओएस ने अपने 2 अगस्त, 2016 के पत्र संख्या 8/(19)/2016-टीएएमपी के द्वारा सूचित किया है कि गांधीधाम टाउनशिप से संबंधित भूमि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव एमओएस द्वारा बनाया जा रहा है। इसलिए, एमओएस ने इस प्राधिकरण को डीपीटी के गांधीधाम टाउनशिप की दर संरचना के संशोधन के डीपीटी के 11 अप्रैल, 2016 के प्रस्ताव को रोके रखने और इस संबंध में एमओएस द्वारा नीति की संसूचना के पश्चात् आरंभ करने का अनुरोध किया। इस संबंध में, एमओएस से अभी कोई नीति प्राप्त नहीं हुई है।

3.3 चूंकि मामला अप्रैल, 2016 से निपटान के लिए लंबित था और यह मानते हुए कि मामले को अनिश्चित काल तक रोक कर नहीं रखा जा सकता, इस प्राधिकरण ने 21 जुलाई, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/25/2016-केपीटी के द्वारा डीपीटी के 11 अप्रैल, 2016 के प्रस्ताव को बंद कर दिया। इस प्राधिकरण ने यह निर्णय दिया कि एमओएस द्वारा संसूचित नई नीति के आधार पर डीपीटी से जब कभी संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होगा उसे नया मामला समझा जाएगा।

3.4 भूमि प्रबंधन हेतु भूमि नीति दिशानिर्देश, 2014 के मुद्दों के बारे में एमओएस द्वारा 14 मई, 2018 के पत्र संख्या पीडी-13017/2/2014-पीडी-IV के द्वारा जारी स्पष्टीकरण परिपत्र (भूमि प्रबंधन) संख्या 2018 का 1 में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या डीपीटी के गांधीधाम टाउनशिप के पट्टा किराये इस प्राधिकरण द्वारा भूमि नीति दिशानिर्देश, 2014 के पैरा 13 के अनुसार नियत किये जा सकते हैं। इसलिये हमारे 20 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या टीएएमपी/25/2016-केपीटी के द्वारा एमओएस को इस मामले में हमें सलाह देने का अनुरोध किया गया था। इसके पश्चात् 25 जनवरी 2019, 06 फरवरी, 2019 और 18 अप्रैल, 2019 को अनुस्मारक भी भेजे गये।

3.5 प्रत्युत्तर में, एम ओ एस ने 03 मई 2019 के अपने पत्र संख्या पीडी-1301/1/2014-पीडी-IV/301170 के द्वारा सूचित किया है कि मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के नगर क्षेत्र के दरमानों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है और प्राधिकरण द्वारा इसी प्रकार का निर्णय डीपीटी के नगर क्षेत्र के बारे में भी लिया जा सकता है। मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के नगर क्षेत्र के दरमानों के निर्धारण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की संसूचना सम्बंधी एम ओ एस के 03 मई 2019 के पत्र की प्रति पत्तन द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिये डीपीटी को भेज दी गयी थी। इसके पश्चात् 21 नवम्बर, 2019 को अनुस्मारक भी भेजा गया है। डीपीटी का उत्तर प्रतीक्षित है।

4.1 चूंकि गांधीधाम टाउनशिप की वर्तमान दरों की वैधता 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त हो गई है, डीपीटी ने अब अपने 25 अक्तूबर, 2019 के पत्र के द्वारा इस प्राधिकरण को 6 महीने की और अवधि के लिए यानी 31 मार्च, 2020 तक वर्तमान दरों को प्रभारित करना जारी रखने का अनुरोध इस शर्त पर किया कि संशोधित दरें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी।

4.2 उक्त को देखते हुए और चूंकि गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त हो गई है, यह प्राधिकरण गांधीधाम टाउनशिप भूमि की वर्तमान दर संरचना को उसकी समाप्ति की तारीख से 31 मार्च, 2020 तक अथवा डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना की तारीख तक जो भी पहले हो, डीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित, विस्तार करता है।

5.1 सरकार द्वारा जारी भूमि नीति दिशानिर्देश 2010 (जिसके आधार पर गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना अप्रैल, 2012 में नियत की गई थी) अनुबद्ध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तब तक होती रहेगी जब तक उनका संशोधन इस प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता। इस प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 2012 में अनुमोदित आदेश में भी इस संबंध में विशिष्ट शर्त निर्धारित की गयी थी। यह शर्त पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित भूमि दिशानिर्देश, 2014 में अभिभावी है। चूंकि मौजूदा पट्टा किराया अनुसूची में जब तक पट्टा किरायों में इस

प्राधिकरण द्वारा संशोधन नहीं किया जाता तब तक पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वृद्धि सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इसलिए 2 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वृद्धि गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की विस्तारित अवधि के दौरान लागू रहेगी।

5.2 फिर भी, इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ मौजूदा पट्टा किरायों का विस्तार वर्तमान परिदृश्य में निर्वात से बचने के लिए अंतरिम व्यवस्था है। इस संबंध में डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर गांधीधाम टाउनशिप के लिए निर्धारित पट्टा किराया को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना होगा, जैसाकि डीपीटी ने अनुरोध किया है।

6. परिणाम में और सामूहिक विचार-विमर्श के उपरांत ऊपर बताये गए कारणों से यह प्राधिकरण, गांधीधाम टाउनशिप भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता को उसकी समाप्ति की तारीख से 31 मार्च, 2020 तक अथवा डीपीटी द्वारा प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./343/19]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 29th November, 2019

**No.TAMP/20/2010-KPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township land of Deendayal Port Trust (DPT) as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No.TAMP/20/2010-KPT

**Deendayal Port Trust**

**Applicant**

### QUORUM

- (i). Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 29<sup>th</sup> day of November 2019)

This case relates to a proposal filed by Deendayal Port Trust (DPT) for extension of the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land of DPT.

2. The validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of DPT was last extended based on the request of DPT vide Order No.TAMP/20/2010-KPT dated 03 May 2019 from the date of expiry till 30 September 2019 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal filed by the DPT, whichever is earlier.

3.1. Para 5.7 of Amended Land Policy Guidelines (LPG) 2014 states that the Policy is applicable for all Major Ports except for land relating to the Township areas of DPT, Mumbai Port Trust (MBPT) and Kolkata Port Trust (KOPT) for which separate policy will be formulated.

3.2. On a reference made to MOS in this regard, the MOS vide its letter no.8/(19)/2016-TAMP dated 02 August 2016 informed that a proposal seeking approval of the Union Cabinet on Land relating to Gandhidham Township was being prepared by the MOS. The MOS, therefore, requested this Authority to keep on hold the proposal dated 11 April 2016 of DPT for revision of rate structure of Gandhidham Township of DPT and take up after the MOS conveys the policy in this regard. No policy from MOS in this regard was received.

3.3. Since the case was pending for disposal since April 2016 and also recognising that the case cannot be kept open indefinitely, this Authority vide Order No.TAMP/25/2016-KPT dated 21 July 2017 closed the proposal dated 11 April 2016 of DPT. This Authority held that the revised proposal as and when received from DPT based on new policy to be communicated by MOS, will be treated afresh.

3.4. The Clarification Circular (Land Management) No.1 of 2018 issued by MOS vide letter No.PD-13017/2/2014-PD-IV dated 14 May 2018 relating to issues on Policy Guidelines for Land Management, 2014 is not explicit whether lease rent for Gandhidham Township at DPT is to be fixed by this Authority following para 13 of the amended Land Policy Guidelines, 2014. Therefore, the MOS was requested vide our letter No.TAMP/25/2016-KPT dated 20 July 2018 to advise us on the matter. This was followed up by our reminders dated 25 January 2019, 06 February 2019 and 18 April 2019.

3.5. In response, the MOS vide its letter No.PD-1301/1/2014-PD-IV/301170 dated 03 May 2019 has informed that a decision on fixation of SOR for Township area of Mumbai Port Trust (MBPT) by TAMP has been taken and similar action for the Township area of DPT may also be taken by TAMP. A copy of the MOS letter dated 03 May 2019 conveying decision taken on fixation of SOR for Township area of MBPT was forwarded to DPT for appropriate action by the port. This was followed up by reminder dated 21 November 2019. Response of DPT is still awaited.

4.1. Since the validity of existing rates of Gandhidham Township expired on 30 September 2019, the DPT has, now, vide its letter dated 25 October 2019 requested this Authority to allow it to continue to charge at the existing rates for a further period of 6 months i.e. upto 31 March 2020, subject to condition that revised rates will be made applicable with retrospective effect.

4.2. In view of the above and since the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land has expired on 30 September 2019, this Authority extends the validity of the existing rate structure of the Gandhidham township land from the date of its expiry till 31 March 2020 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier as sought by DPT.

5.1. The Land Policy Guidelines of 2010 issued by the Government (based on which the rate structure for Gandhidham Township Land has been fixed in April 2012) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order passed by this Authority in April 2012 also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the amended Land Policy Guidelines, 2014 issued by the Ministry of Shipping. Since, the existing Schedule of lease rent already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by this Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Gandhidham Township Land.

5.2. However, it is to be noted in this regard that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Gandhidham Township based on the proposal to be filed by the DPT in this regard will have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

6. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land from the date of its expiry till 31 March 2020 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./343/19]